कसमें वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं, बातों का क्या मंत्री कृष्णपाल गूजर!

फ़रीदाबाद (म.मो.) चुनाव सिर पर आ गये। काम-धाम कुछ किया नहीं। सत्ता हाथ से सड़कती देख भाजपा नेतृत्व ने मंत्रियों विधायकों व सांसदों की कसी नकेल। सबको दौड़ाया फ़ील्ड में, झूठे-सच्चे वादे करने व कसमें खाने के लिये। परंतु ज़मीनी हकीकत से दो-चार होने वाली जनता बखूबी समझती है कि बातों का क्या?

जनता को बरगलाने के लिये उक्त तमाम नेतागण हर रोज़ कहीं न कहीं भाषणबाज़ी करके जो झूठ परोस रहे हैं उसे अधिकाधिक जनता तक पहुंचाने के लिये पूरे मीडिया को काम पर लगा रखा है। यदि कभी भाषणबाज़ी का जुगाड़ नहीं हुआ तो होटलों में प्रेस वार्ता के द्वारा अपनी चुनावी जुमलेबाज़ी को जनता तक पहुंचाने का पुरज़ोर प्रयास किया जा रहा है। ऐसी ही एक पत्रकार वार्ता में स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने विधायक सीमा त्रिखा व मूल चन्द को साथ लेकर बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गांव, किसान व ग़रीब के कितने बड़े हमदर्द हैं। किसान की फ़सल का समर्थन मूल्य बढा कर उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन तमाम ग्रामीण, किसान व ग़रीब समझते हैं कि ये चुनावी जुमले हैं, जुमलों का क्या?

वैसे मोदी की जिस ऐतिहासिक घोषणा का बखान मंत्री जी ने किया इसकी शुरूआत 1965 के आस-पास हो गयी थी जब सरकार ने पहली बार गेहूं व धान का समर्थन मूल्य घोषित किया था, जो हर 2-4 साल बाद बढता गया। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ ज्यों-ज्यों भ्रष्टाचार बढ़ता गया किसानों को मिलने वाले इस समर्थन मूल्य में सेंधमारी बढती गयी। मोदी एवं खट्टर सरकार के बीते चार वर्षों में यह सेंधमारी बढकर चरम सीमा पर पहुंच गयी। हाल ही में बढाये गये एतिहासिक समर्थन मूल्य ने तो उस चरम सीमा को भी तोड़ दिया क्योंकि घोषित बढ़े हुये समर्थन मूल्य में किसान को धेला भी नहीं मिला, सब बिचौलियों की जेब में जाता रहा।

इसी तर्ज पर एक और नौटंकी करते हुये मंत्री गूजर ने ज़िला फ़रीदाबाद व पलवल के उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों, सिविल सर्जनों व अन्य अधिकारियों की बैठक में आदेश दिये कि वे गांव-गांव, गली-गली जाकर बच्चों,बूढों में बीमार पड़े लोग़ों को ढूंढ लायें और उनका इलाज करें। खासकर आंखों के मोतिया बिंद के रोगियों को ढूंढ कर लायें, उनके मुफ़्त ऑपरेशन कर चश्मा भी फ्री में लगा कर देवें। इस काम के लिये तुरंत दो मेडिकल वैन काम पर लगाने को भी कहा।

चुनावी मौसम में जनता को बहकाने के लिहाज़ से तो गूजर की यह नौटंकी सही हो सकती है यदि लोग इनके बहकावे में आ जायें तो। पर वे तमाम लोग बहकावे में आयेंगे कैसे जो हर रोज बीके जैसे तमाम सरकारी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में धक्के खाते घूम रहे हैं? वे लोग कैसे बहकेंगे जिनकी डिलिवरियां अस्पतालों के दरवाज़ों पर होती हैं? सरकारी अफ़सरों को मरीज़ ढूंढ कर लाने की कतई जरूरत नहीं है, मरीज़ तो खुद चल कर अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, गूजर जी की सरकार पहले उन्हें तो सम्भाल ले। मंत्री जी तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनके अस्पतालों में मरीज़ हैं ही नहीं और डॉक्टर खाली बैठे हैं। जिस बीके में कम से कम 150 डॉक्टर होने चाहिये वहां केवल 30 मौजूद हैं। जब एक डॉक्टर को 100-150 मरीज देखने पड़ें तो वह क्या मरीज़ देखेगा?

सेक्टर 8 का ईएसआई अस्पताल हरियाणा सरकार के नियंत्रण में है। इसके कुल खर्च का 88 प्रतिशत ईएसआई निगम व शेष हरियाणा सरकार को वहन करना होता है। परंतु अपने 12 प्रतिशत को बचाने के लिये हरियाणा सरकार ने इस 200 बैड वाले अस्पताल को मात्र 50 बैड का बनाकर बर्बाद कर रखा है। मजे की बात तो यह है कि डॉक्टरों, अन्य स्टाफ़ व उपकरणों की कमी के चलते 50 बैड में से भी मात्र 10-12 बैड ही भर पाते हैं। जब वहां है ही कुछ नहीं तो कोई मरीज़ वहां करने क्या जायेगा? इससे भी बद्तर हाल है ईएसआई समेत तमाम सरकारी डिस्पेंसरियों का, बातें करते हैं गांव गलियों से मरीज़ ढूंढ कर लाने की। **जिस मंझावली पुल को 31 दिसम्बर 2018 तक चालू करने की बातें गूजर महोदय बड़ी छाती ठोक कर करते थे अब उस पर चुप हैं, हां अपने चेलों से जरूर कहलवा रहे हैं कि 'जल्दी' चालू हो जायेगा।**

बातों के पकौड़े तलने में मंत्री विपुल गोयल भी भला कैसे पीछे रहते

स्थानीय विधायक एवं उद्योग मंत्री गोयल ने भी पार्टी हाईकमान के आदेशों का पालन करते हुय यथासंभव झूठ के पकौड़े तलने शुरू कर दिये हैं। ऐसी ही एक कढाई उन्होंने गत सप्ताह स्थानीय आईटीआई में चढाई। इसमें सफ़ेद झूठ बोलते हुये कहा कि 32000 युवकों को नौकरी दे दी गयी है और 50000 अन्य को देने के लिये जय भारत मारूति, जगुआर, जी 4, ओला व ऊबर आदि कम्पनियों के साथ एमओयू साइन कर लिया गया है।

सभी जानते हैं कि ओला व ऊबर दोनों प्राइवेट टैक्सी कम्पनियां हैं। इनके यहां कभी भी कोई भी अपनी कार को अटैच करके बतौर टैक्सी चला सकता है और बहुत से लोगों ने यह काम कर भी रखा है। इसी तरह तमाम अन्य कम्पनियां भी अपनी जरूरतों के मुताबिक ठेकेदारी व कैजुअल में भर्ती करती हैं, आईटीआई वालों को वे बतौर प्रशिक्षु रख कर, काम सिखाने के नाम पर उनका खूब शोषण करती हैं। इसके लिये उन्हें किसी मंत्री के साथ एमओयू की कतई कोई जरूरत नहीं।

हां मंत्री जी यदि, हज़ारों शिक्षकों, क्लर्कों, डॉक्टरों, नर्सों रोडवेज में ड्राइवर व कंडक्टरों आदि के बरसों से रिक्त पड़े पदों को भरने की कोई बात करते तो समझ में आता कि हरियाणा सरकार कुछ कर रही है। सरकारी पदों के रिक्त पड़े रहने से जो सेवायें प्रभावित हो रही हैं उनका तो सरकार कुछ ख्याल करे, रोजगार का ना सही।

बिना उपकरण व स्टाफ़ बढाये ईएसआई कार्पोरेशन की चिकित्सा सेवा का रैफ़रल घटाने पर ज़ोर

नई दिल्ली (म.मो.) दिनांक 17 जुलाई को ईएसआई कार्पोरेशन के डीजी (डायरेक्टर जनरल) व भारत सरकार के श्रम सचिव ने वीसी (वीडियो कांफ्रेंस) के जरिये देश भर में फ़ैले अपने अस्पतालों खासकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को हिदायत दी कि वे अपने यहां आने वाले मरीज़ों को निजी अस्पतालो में रैफ़र करने की अपेक्षा स्वयं पूरा इलाज करें। विदित है कि निजी अस्पतालों को रैफ़र किये जाने की वजह से ईएसआई निगम को देश भर में करीब 700 करोड़ के बिलों की पेमेंट करनी पड़ती है। अकेले एनसीआर (दिल्ली के आसपास) क्षेत्र में ही करीब 200 करोड़ की पेमेंट है।

इस तरह की हिदायत, मुख्यालय से अक्सर आती रहती हैं। इसके दबाव में गुड़गांव के ईएसआई अस्पताल अपने मरीज़ों को निजी अस्पतालों की अपेक्षा सफ़दरजंग अस्पताल में रैफ़र करते आ रहे हैं जबकि यह बिल्कुल अनुचित एवं गैरकानूनी तथा मज़दूरों के साथ विश्वासघात है। मज़दूर अपने वेतन का साढे छः प्रतिशत हर माह ईएसआईसी को सफ़दरजंग में इलाज कराने के लिये नहीं देता। वहां जाने के लिये उसे ईएसआई से रैफ़र कराने की कोई जरूरत नहीं है, वह सीधे भी जा सकता है। ईएसआईसी मज़दूर को एक बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के नाम पर उससे हर माह वसूली करती है।

जानकर सूत्रों के अनुसार तमाम मेडिकल कॉलेजों के डीन साहेबान ने एक स्वर में बताया कि वे रैफ़रल तभी समाप्त कर सकते हैं जब उन्हें पर्याप्त उपकरण, साजो-सामान और आवश्यक स्टाफ़ उपलब्ध हो; उसके बिना वे अपने मरीज़ों को मरने के लिये नहीं छोड़ सकते। कुछ अस्पतालों ने बताया कि उनके द्वारा मांगे गये सामान व स्टाफ़ की फ़ाइलें 2-2 साल तक मुख्यालय में घूमती रहती हैं। वहां बैठे निकृष्ट एवं नालायक अधिकारी फ़ाइलों में अड़ंगे लगाना ही अपना एक मात्र उद्देश्य समझते हैं।

समझा जा रहा है कि केन्द्रीय श्रम सचिव एवं डीजी ने मुद्दे को गंभीरता से लेते हुये कहा कि आगे से वे अपनी मांगे (फ़ाइलें) सीधे उनके पास भेजा करें और वे सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यालय में कुंडली मारे बैठे अधिकारी उन पर तत्परता से काम करें। अस्पतालों की एक अन्य शिकायत को दूर करते हुये उन्होंने कहा कि जो भी उपकरण खरीदा जाय वह आधुनिकतम और बेहतरीन हो, ठीक वैसे ही जैसे एम्स में खरीदे जाते हैं। जबकि मुख्यालय में बैठे नालायक अधिकारी सदैव सस्ते उपकरण ही खरीदने की फ़िराक में रहते हैं जो आये दिन खराब हुए रहते हैं। जाहिर है ऐसे में मरीज़ों को बाहर रैफ़र करना ही पड़ता है।

चंद बेहतरीन उपकरणों व बढिया स्टाफ़ के चलते फ़रीदाबद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनी (प्रसव) विभाग का रैफ़रल लगभग ज़ीरो हो चुका है। प्रसव वाली महिलाओं को पहले इसलिये भी रैफ़र करना पड़ता था कि नवजात शिशुओं की देखभाल के लिये लिये न तो यहां नर्सरी थी और न ही शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर। अब गायनी विभाग के साथ-साथ शिशु नर्सरी एवं विभाग के सुचारु रूप से चलने की वजह से रैफ़रल लगभग बंद हो गया है।

इसी तरह यदि अन्य विभागों में भी आवश्यकतानुसार उपकरण एवं स्टाफ़ उपलब्ध कराया जाय तो वहां भी रैफ़रल को रोका जा सकता है। जानकार बताते हैं कि गायनी विभाग की प्रमुख विशेषज्ञ डॉ. ऊषा ने अपने विभाग की आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिये करीब दो साल तक चक्कर लगाये थे। कई बार उनकी फ़ाइल ही गुम करा दी जाती थी मुख्यालय द्वारा।

मुख्यालय की ओछी हरकतों से लगने लनता है कि वे चाहते ही नहीं कि रैफ़रल बंद हो। शायद रैफ़रल बिलों की पेमेंट में से उन्हें भी कुछ कट मिलता होगा।

हरियाणा टूरिज़्म के पेट्रोल पंप सभी नियम कानूनों से ऊपर

फ़रीदाबाद (म.मो.) सरकारी विभाग अपने आपको कैसे सभी नियम कानूनों से ऊपर मानते हैं, इसका एक उदाहरण इस संवाददाता को पिछले दिनों देखने को मिला। संवाददाता ने एनआईटी 3 नम्बर स्थित गोल्फ़ कल्ब फिलिंग स्टेशन से अपनी गाड़ी में डीजल भरवाया। यह पेट्रोल पंप हरियाणा सरकार के टूरिज़्म विभाग द्वारा संचालित है। जब डीजल भरने के पश्चात गाड़ी के विंड स्क्रीन साफ़ करने को कहा गया तो उस कर्मचारी ने साफ़ मना कर दिया कि जी ये सरकारी पंप है। यहां कोई वाइपर नहीं मारता शीशों पे।

जब इस बाबत मैनेजर रूम में बैठे व्यक्ति से बात की गयी तो उसका भी शुरू में यही जवाब था कि ये सरकारी पंप है और हम नहीं ये काम करते। लेकिन जब उससे शिकायत पुस्तक देने को कहा गया तो उसने कहा कि जी आपकी गाड़ी में कपड़ा मरवा देता हूं।

इसके उपरांत उसने एक सफ़ाई कर्मचारी को बुलाकर गाड़ी के शीशे साफ़ करने को कहा। वो बेचारा कहीं से ढूंढ-ढांढ कर एक बेहद सड़ा कपड़ा उठा कर लाया और उससे शीशे साफ़ किये। जाहिर है कि पंप पर विंड स्क्रीन साफ़ करने का वाईपर और जो बाल्टी पानी से भरी होनी चाहिये, वो नहीं थी।

बता दें कि हर पेट्रोल पंप पर साफ़ पीने का पानी, पेशाब घर, गाड़ियों के टायरों में हवा भरने को इन्तजाम, पक्का बिल और आपकी गाड़ी का अगला पिछला शीशा साफ़ करने का इन्तजाम जरूरी है। ये उनकी डीलरशीप की शर्तों में शामिल है। इनमें से कोई एक भी सुविधा नहीं प्रदान करने पर पेट्रोल पंप की एलाटमेन्ट रद्द की जा सकती है। लेकिन हरियाणा टूरिज़्म के फ़रीदाबाद स्थित दोनों पंपों पर इनमें से कोई सुविधा नहीं है फ़िर भी ये धड़ल्ले से चल रहे हैं।

यह भी बताया जाता है कि इन 'सरकारी पंपों' पर भी मिलावट और चोरी उतनी ही है जितनी और पंपों पर। इस कारण होने वाली कमाई के चक्कर में टूरिज़्म के कर्मचारी मोटी रिश्वत देकर भी यहां तैनात होना चाहते हैं, ऐसा भी बताया जाता है। क्या जनता के साथ होने वाली इस धोखाधड़ी और सरकारी विश्वासघात पर कोई तेल कंपनी ध्यान देगी?

चुनावी ढोल और विकास के झुनझुने!

बल्लबगढ़ (म.मो.) भाजपा हाई कमान के आदेश पर सभी मंत्री, सांसद व विधायक जनता को बरगलाने के लिये हर रोज़ तरह-तरह के शगूफ़े छोड़ रहे हैं। गत चार वर्षों में तो कुछ किया धरा नही, अब चुनाव सिर पर आये देख कर, वोट मांगने लायक मुंह बनाने के लिये तथाकथित विकास की नौटंकी करने में जुटे हैं।

इस क्रम में राज्य के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने बीते सप्ताह पृथला विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र में एक-दो नहीं पूरे तीन आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का शिलान्यास किया। शिलान्यास ही किया है जैसा कि केन्द्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी 15 अगस्त 2014 को यमुना किनारे मंझावली पुल का कर गये थे। इन शिलान्यासों पर आईटीआई अब खड़ी होंगी भी या नहीं, कोई नहीं जानता। हां चुनाव में वोट मांगते वक्त कहा जा सकेगा, देखो हमने तुम्हारे लिये 3-3 आईटीआई खोलने की योजना बना दी। तुर्रा यह भी साथ में है कि यहां से बेशक भाजपा का उम्मीदवार हार गया था फ़िर भी भाजपा सरकार ने यहां विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी।

नकली विकास की श्रृंखला को आगे बढाते हुये विपुल ने कहा कि इसी क्षेत्र में स्किल डवलेपमेंट यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है जिससे युवक अपने हुनर को बढा कर रोज़गार के अच्छे अवसर प्राप्त कर पायेंगे। विदित है कि इस यूनिवर्सिटी का ढोल भाजपा सरकार बीते 3 वर्षों से पीट रही है, परन्तु परिणाम जीरो का जीरो। हुनर बढाने के नये संस्थान खोलने की नौटंकी तो सरकारी भांड कर ही रहे हैं परन्तु जो संस्थान-आईटीआई व यूनिवर्सिटियां पहले से मौजूद हैं, उनकी हालत क्या है? न तो वहां पर्याप्त स्टाफ़ है न पर्याप्त उपकरण। युवा वहां दाखिला लेकर अपना समय बर्बाद करके बेरोजगारों की लाइन में लग जाते हैं।

विपुल गोयल जब ढोल पीटने में जुटे हों तो क्षेत्र का विधायक टेक चंद भला पीछे कैसे रह सकता है। यद्यपि वह बहुजन समाज पार्टी से हैं लेकिन पहले दिन से ही भाजपा सरकार की गोद में बैठे हैं। काफ़ी 'समझदार' हैं, समझते हैं कि जो कुछ मिलेगा सत्ता से ही मिलेगा, लिहाजा इसी के इर्द-गिर्द रहने में ही लाभ है। बीते सोमवार को उन्होंने भी मोहना के नवनिर्मित महिला कॉलेज में हवन यज्ञ आदि करके प्रथम सत्र का शुभारंभ करा दिया। मोहना गाव को कॉलेज देने का नाम तो कर दिया परन्तु इसमें पढाने वाला कोई नहीं। प्रिंसिपल प्रीता को भी नेहरू कॉलेज फ़रीदाबाद से बुला कर हवन में बैठा दिया। वे 6000 की संख्या वाले अपने नेहरू कॉलेज को संभालेगी या 30 किलोमीटर दूर स्थित कॉलेज को? फ़िर इस कॉलेज में संभालने को है भी क्या? जब पढाने वाला स्टाफ़ ही नहीं तो पढने वाली लड़किया भी घर से कितने दिन तक आ पायेंगी? ऐसे में कॉलेज में केवल यज्ञ-हवनों से ही काम चलाना पड़ेगा।

कुल मिलाकर यह सब चुनावी पाखंड है, जनता यदि इस बहकावे में आ जाती है तो फ़िर से भाजपा की पौ बारह हो सकती है।

स्कूल के गुनहगार ही हिसाब भी मांगेंगे

चंडीगढ़ (म. मो.) हरियाणा में स्कूल की दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा के लचर परिणाम में नया जानने को बेशक कुछ भी नहीं है लेकिन राज्य का शिक्षा विभाग इसके कारण जानने का ड्रामा करने जा रहा है। राज्य के दोनों स्मार्ट सिटी, फरीदाबाद और करनाल समेत आठ जिले तो ऐसे हैं जहाँ के तमाम स्कूलों में दस प्रतिशत विद्यार्थी भी उत्तीर्ण नहीं हुए।

करनाल स्वयं मुख्यमंत्री खट्टर का और फरीदाबाद राज्य से केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल का क्षेत्र हैं। राज्य से दूसरे केन्द्रीय मंत्री इन्द्रजीत का जिला रेवाड़ी भी इस सन्दर्भ में सुर्खियाँ बटोर रहा है। वहां एक राजकीय कन्या उच्चतर स्कूल में महज एक अध्यापक और एक विद्यार्थी हैं। यहाँ तक कि राज्य के शिक्षा मंत्री रामबिलास का जिला महेंद्रगढ़ भी दस प्रतिशत की लिस्ट में दिखाई देगा।

इतना बुरा हाल क्यों है, यह जानने के लिए शिक्षा विभाग की टीम सम्बंधित जिलों में जाकर अधिकारीयों और प्रिंसिपल से मीटिंग करेंगी। यानी सारे गुनाहगार ही हिसाब-किताब करेंगे और निदान सुझायेंगे।

स्कूलों की दुर्दशा के कारण जग-जाहिर हैं। सबसे बढ़ा तो नीतिगत कारण है- सरकारी स्कूलों को मरने दो ताकि प्राइवेट स्कूलों की कमाई पर आंच न आये। प्राइवेट स्कूलों की लूट में राजनेताओं और अफसरों का हिस्सा बंधा होता है। बहुत से तो स्वयं मालिक भी होते हैं।

सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं होते, जो हैं भी अपनी मर्जी से आते-जाते हैं, तबादले जरूरत के मुताबिक नहीं राजनीतिक सुविधा से होते हैं, न बिल्डिंग का रखरखाव है न अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जाता है। अध्यापकों की क्षमता बढ़ाने को सिर्फ खाना-पूर्ति के दायरे में धकेल कर इति हो जाती है। साफ-सफाई और बच्चों की सुरक्षा राम भरोसे ही रहती है। स्कूलों को लेकर नयी घोषणा करने में क्या विधायक और क्या मंत्री सब आगे दिखेंगे। जो जितना गुनाहगार है उतना बढ़-चढ़ कर। ऐसे में दस प्रतिशत परिणाम भी आना, चमत्कार से कम नहीं।